भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि आधारित उद्योग

डॉ. तरुण बाबू श्रीवास्तव

नमूना • SAMPLE

अखण्ड पब्लिशिंग हाउस
दिल्ली (भारत)

द्वारा प्रकाशित

अखण्ड पब्लिशिंग हाउस

एल-9ए, प्रथम तल, गली न. 42,
सादतपुर एक्सटेंसन, दिल्ली-110094 (भारत)
Phone : 9968628081, 9013387535
E-mail : akhandpublishinghouse@gmail.com
akhandpublishing@yahoo.com
Website : www.akhandbooks.in

भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि आधारित उद्योग

Bharateey Arthvyawastha Aur Krishi Aadharit Udhyog
by Dr. Tarun Babu Sreevastava

आईएसबीएन : 978-81-19098-52-1
सर्वाधिकार : © डॉ. तरुण बाबू श्रीवास्तव
संस्करण : प्रथम, 2025, जून 04

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से को प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य माध्यम द्वारा पुनः प्राप्ति समेत किसी भी रूप में प्रतिलिपिकृत, अनुवादित, संगृहीत नहीं किया जा सकता है और न ही किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम द्वारा इसे प्रसारित किया जा सकता है।

इस पुस्तक में लेखक द्वारा व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं जिसका प्रकाशक से कोई संबंध नहीं है।

भारत में प्रकाशित

झपसू यादव द्वारा 'अखण्ड पब्लिशिंग हाउस' के लिए प्रकाशित। वी.एम. ग्राफिक, दिल्ली द्वारा कवर डिजाइन व शब्द संयोजन तथा आरना इंटरप्राइजेज, दिल्ली से मुद्रित।

SAMPLE COPY

समर्पण

पूज्य पिता

श्री मंगल प्रसाद श्रीवास्तव जी

एवं

ममतामयी माता

श्रीमती दर्शन श्रीवास्तवजी

के चरणों में सादर समर्पित करता हूँ।

धर्मपत्नी

श्रीमती तृप्ति सिंह

व

पुत्र

कृष्णव सिंह श्रीवास्तव

के निरन्तर सहयोग के बिना यह संभव नही था।

—डॉ. तरुण बाबू श्रीवास्तव

(आचार्य व चिंतक)

SAMPLE

नमूना • SAMPLE

विषय-सूची

	भूमिका	*vii*
1.	प्रस्तावना	1
2.	जनपद बुलन्दशहर की सामान्य रूपरेखा	38
3.	कृषि आधारित उद्योगों का वर्गीकरण	51
4.	चयनित क्षेत्रों की स्थिति	61
5.	कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार	81
6.	कृषि आधारित उद्योगों के लियें वित्त प्रबन्ध	99
7.	कृषि आधारित उद्योगों का विपणन	119
8.	कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार	133
	संदर्भ ग्रंथ सूची	*157*

नमूना • SAMPLE

नमूना • SAMPLE

भूमिका

कृषि आधारित उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। कृषि आधारित उद्योग न केवल किसानों की आयों को बढ़ाने में सहायक है वरन कृषकों को खाली समय में भी बेहतर रोजगार उपलब्ध करने में सहायक है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, "कृषि एवं कृषि उद्योग कुल रोजगार का दो तिहाई भाग प्रदान करते है।" वास्तव में इस क्षेत्र पर ध्यान दिये बिना हम ग्रामीण विकास नही कर सकते है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी और कृषि पर अतिरिक्त श्रम को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाने से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिये ग्रामीण उद्योगों और उनसे संबंधित क्रियाओं का विकास किया जाना परमावश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों का और विस्तार बहुत कुछ कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार प्रसार पर निर्भर करेगा। इन उद्योगों का प्रमुख अंश विनिर्माण क्षेत्र है जिनमें कृषि आधारित उद्योग वस्त्र उद्योग, निर्माण पदार्थो में लगे उद्योग शामिल है। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमानें के उद्योगों में अधिक रोजगार के प्रसार की सम्भावनायें नजर नहीं आतीं परन्तु लघु क्षेत्र में रोजगार अवसर पैदा करने की बहुत सम्भावनायें है ।

कृषि आधारित उद्योग शक्ति अर्थव्यवस्था के विकेन्द्रीकरण और सन्तुलन को बनाने में शक्तिशाली यन्त्र की भांति कार्य करते है और कृषि और उद्योगों के मध्य पिछड़े और विकसित उद्योगों के बीच बड़े स्तर पर खाई पाटने का कार्य करते है। "ग्रामीण औद्योगिकरण, ग्रामीण विकास और समृद्धि की सूचक है।" ये उद्योग गांवो से शहरों में होने वाले पलायन को रोककर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करते है। ये उद्योग बड़े पैमाने पर तत्काल काम जुटाते है, राष्ट्रीय आय के अपेक्षाकृत अधिक न्यायपूर्ण वितरण का आश्वासन देते है, पूंजी और कौशल के साधनों को प्रभावशाली ढंग से गति देते है और ग्रामीणों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाते है ग्रामीण औद्योगिकरण ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में फैली अत्यधिक बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रयोग को जिला स्तर पर घरेलू बाजारों में प्रयोग किया जा सकता है। केवल परम्परागत पद्धति ही काफी नहीं है बल्कि उन्नत तकनीक और वित्त संबंधी सुविधा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है।

कृषि आधारित उद्योग, बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है ये उद्योग आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को कम करके आय एवं सम्पत्ति की असमानताओं को कम करने में सहायक है तथा आर्थिक गतिविधियों के विकेंद्रीयकरण के द्वारा प्रादेशिक असंतुलनों को भी कम करते है। लघु एवं कुटीर उद्योग विशेषकर कृषि आधारित उद्योग उपभोग वस्तुओं की आपूर्ति में नीव वृद्धि लाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते है। ये कम पूंजी के साथ शुरू किये जा सकते है इनकी स्थापना में कम समय लगता है। और इनकी

SAMPLE

उत्पादन प्रकिया इस प्रकार की होती है कि अपेक्षाकृत कम समय में ही उपभोग वस्तुयें उपलब्ध होने लगती है।

इन उद्योगों के माध्यम से देश के भुगतान शेष पर कम दवाब पड़ेगा और ये विदेशी मुद्रा कमाने में विशेष सहायक हो सकते है देश के भुगतान से संबंधी स्थिति बहुत खराब पड़ी हुई है। निर्यात की तुलना में आयात बहुत अधिक होने के कारण हमें भुगतान शेष में भारी घाटा होता रहा है जिसके फलस्वरूप देश में विदेशी मुद्रा की बड़ी कमी होती रही है। लघु उद्योगों का विकास यहां भी बहुत सहायक हो सकता है। इनके विकास के लियें विदेशी साजो-सामान के आयात की आवश्यकता बहुत कम होती हैं यही नहीं बल्कि निर्यात सम्वर्धन में बहुत योगदान दे सकते है अनेक विदेशी मंडियों में इनके द्वारा विनिर्मित वस्तुयों की बढ़ी मांग है और इनका निर्यात तेजी से बढ़ रहा है।

कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। विकासशील अर्थव्यवस्था में व्यापक बेरोजगारी, अल्पबेरोजगारी एवं गांवो से शहरों की ओर श्रमिकों के पलायन आदि समस्याओं को ग्रामीण उद्योग विशेषकर कृषि आधारित उद्योग को लगाकर दूर किया जा सकता है ये उद्योग कृषि श्रमिकों को खाली समय में बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करते है और कृषि के मशीनीकरण में भी सहायक है।

मेरा अध्ययन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनेक पहलूओं को समेटे हुये एक अलग अध्ययन होगा। मेरा शोध कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के परिणामस्वरूप ग्रामीण व्यवसायों, आय, मजदूरी, प्रवास, जोत पद्धतियों, रोजगार आदि पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालेगा। मेरा वर्तमान शोध के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है

जनपद में उन कारकों का पता लगाना जो कृषि आधारित उद्योगों का विकास एवं ग्रामीण रोजगार पर उनसे पड़ने वाले रोजगार से संबंधित है, कृषि आधारित उद्योग एवं जोत पद्धतियों के बीच संबंधों की जांच करना, कृषि उद्योगों की स्थापना के परिणामस्वरूप जनपद में ग्रामीण जनता के व्यवसायिक ढ़ाचे में परिवर्तन का अध्ययन करना, ग्रामीण जनता के आय स्तर में परिवर्तन का अध्ययन करना, विशेष रूप से उन कृषकों, कृषि श्रमिकों एवं अन्य श्रमिकों का जो कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित है. कृषि आधारित उद्योगों के स्थापना के परिणामस्वरूप प्रवास की प्रवृतियों का विभिन्न पहलूओं से विश्लेषण करना जैसे ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरों से ग्रामीण एवं शहरों से शहरों में प्रवास, विभिन्न कृषि आधारित उद्योगों के प्रभावों का तुलनात्मक विशलेषण करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि उद्योगों को प्रभावशाली बनाने हेतू उचित एवं प्रभावी उपायों को सुझाना, व्यक्तिगत रूम से मैंने विभिन्न कृषि आधारित उद्योगों की इकाईयों में महीनों जाकर उनमें कार्यरत श्रमिकों की कार्यदशाओं का समीपता से देखा और समझा है व्यक्तिगत प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैंने अन्य व्यक्तिगत पहलुओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर मैंने जिला उद्योग केन्द्र बुलन्दशहर, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी बुलन्दशहर, में जाकर इन कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठकर विभिन्न कृषि आधारित उद्योगों की समस्याओं के तकनीकी एवं व्यवहारिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया है इस प्रकार मैंने अथक परिश्रम करके जनपद के कृषि आधारित उद्योग की समस्याओं का अध्ययन किया।

मेरा यह विश्वास है कि मैंने जिन कमियों एवं त्रुटियों को इस शोध-प्रबन्ध के माध्यम से इंगित किया है। यदि उनका मेरे सुझाये हुये तरीकों अथवा अन्य किसी सम्मानजनक तरीकों से समाधान कर लिया जायें तो

जनपद में यह उद्योग कृषकों के कल्याण के साथ-साथ भारत के आर्थिक उत्थान में भी सहायक हो सकते है।

इस शोध ग्रन्थ की अथ से इति तक की यात्रा में सबल बने, निर्देशक डॉ. शेखर शर्मा, रीडर, वाणिज्य विभाग एन.आर.ई.सी. कालिज, खुरजा को सर्वोपरि मानता हूँ जिनकी विशेष अनुकम्पा से ही यह सम्भव हुआ। इनकी अनुकम्पा के अभाव में यह शोध ग्रन्थ अंधकार के गर्त में पड़ा होता यदि इन्होने समय-समय पर मेरे कार्य में सहयोग नही किया होता है। अपनें अमूल्य एवं व्यस्त समय में से मुझे समय देकर मेरे शोध कार्य पूर्ण कराया। उनके द्वारा प्रदत्त प्रेरणायें, समय-समय पर दी गई शिक्षायें और दिशायें मुझे अपनें सकल्प के स्पर्श करनें तक निरन्तर गतिवान बनाती रही। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनें के लियें मेरी लेखनी भी मूक है।

मुझे समय समय पर धर्मपत्नी श्रीमती तृप्ति सिंह ने मेरा मनोबल बढ़ा कर मुझे प्रोत्साहित किया।

अन्त में, मैं परम पिता परमात्मा के प्रति नमन करते हुए उन सभी मित्रों तथा सम्बन्धियों का स्मरण करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ, जिनसे प्रत्यक्ष अथाव परोक्ष रूप से मुझे शोध-कार्य में सहायकता मिली। मैं उन सभी विद्वानों, लेखकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ।

'थकना नहीं, रूकना नहीं,
आगे ही आगे बढ़ते जाना है,
क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत आना है।'

—डॉ. तरुण बाबू श्रीवास्तव

SAMPLE

नमूना • SAMPLE

1

प्रस्तावना

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है पिछले दो दशकों से अधिक अवधि में औद्योगिकरण के सगंठित प्रयास के बावजूद कृषि का गौरवपूर्ण स्थान बना हुआ है। 102 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले इस देश में 69 प्रतिशत से अधिक लोग गाँवों में रहते है और कृषि कार्यो से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़े हुये है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसकी 25 प्रतिशत के लगभग हिस्सेदारी है, जिससे हमारी दो-तिहाई जनसंख्या को रोजगार मिलता है। खाद्य-वस्तुएं, चारा कृषि से ही प्राप्त होता है। बहुत से छोटे-बड़े उद्योग कच्चे माल के लिये कृषि पर ही निर्भर है। विदेशी व्यापार भी खाद्य-वस्तुयें व कच्चे माल के निर्यात के लिये कृषि पर ही निर्भर है। इस प्रकार यह कहना अनुचित न होगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। भारतीय सभ्यता का इतिहास अन्य देशों से पुराना है। इसकी कृषि कई शताब्दी पहले ही सापेक्षिक दृष्टि से परिपक्वता की स्थिति में पहुंच चुकी थी।[1]

ब्रिटिश शासको के औपनिवेशिक नीति के फलस्वरूप इस देश में कृषि का कोई विकास नहीं हुआ और मिलों से बने माल की बिक्री से भारतीय अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों के हथकरघा चर्खा उद्योग, कुटीर उद्योग पूरी तरह नष्ट हो गये। समस्त भारत की अर्थव्यवस्था में जो कृषि और निर्माण उद्योगों का सहयोग था, वह भी समाप्त हो गया। इस प्रकार स्वतन्त्रता से पूर्व कृषि व्यवसाय "जीवन निर्वाह' का साधन मात्र बनकर रह गया। यह स्थिति काफी समय तक बनी रही। वस्तुत: 1966 के बाद हरित क्रान्ति के आगमन से स्थिति में कुछ बदलाव आया और कुछ किसानों ने कृषि को व्यावसायिक आधार पर अपनाया। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कृषि आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखती है।

प्रथम विश्वयुद्ध के समय भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग दो तिहाई भाग कृषि से प्राप्त होता था। इसका प्रमुख कारण भारत का औद्योगिक विकास न होना था। स्वतन्त्रता के बाद, विशेष तौर पर योजनाओं का लागू करने के बाद से, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों के विकास के कारण कृषि का हिस्सा लगातार कम होता गया है। 1950-51 में कुल देशीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा (1980-80 की कीमतो पर) 55.4 प्रतिशत 2 था। परन्तु जैसे-जैसे औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने गति प्राप्त की, राष्ट्रीय आय में कृषि के भाग में तीव्र गिरावट आयी और यह 1996-97 में 26 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहुँच गया परन्तु आज भी (2003-04) सकल देशीय उत्पाद का 24 प्रतिशत हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता को

SAMPLE

बताता है। राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है यद्यपि विकसित देशों में कृषि बहुत विकसित है तथापि इन देशों की कृषि पर निर्भरता बहुत कम है। उदाहरण के लिये-इंग्लैड में 2 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 प्रतिशत, कनाडा में 4 प्रतिशत और आस्ट्रेलिया में कृषि से केवल राष्ट्रीय आय का केवल 5 प्रतिशत ही प्राप्त होता है। इस प्रकार जैसे-जैसे कोई देश विकास करता है उसकी कृषि पर निर्भरता कम होती जाती है।[3]

भारत की राष्ट्रीय आय का इतना बड़ा भाग पैदा करने वाला यह क्षेत्र रोजगार और जीवन निर्वाह की दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण ठहरता है। खेती यहां के लोगों का सर्वप्रमुख व्यवसाय है। जनगणना द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ो से पता चलता है कि जहां 1951 में कुल कार्यकारी जनसंख्या का 69.5 प्रतिशत कृषि व कृषि आधारित उद्योगों में कार्यरत था वही 1991 में यह प्रतिशत थोड़ा गिरकर 68 प्रतिशत रह गया। परन्तु जनसंख्या में तेज वृद्धि होने के कारण, कृषि में लगे हुये लोगों की वास्तविक संख्या में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों का उपयुक्त विकास न होने के कारण उनमें रोजगार अवसरों में वृद्धि बहुत कम हो पाई है जिससे मजबूरन बहुत से लोगों को रोजगार हेतु कृषि पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि भूमि पर उनकी सीमांत उत्पादकता बहुत कम है। अधिकतर अल्पविकसित देशों मे कार्यकारी जनसंख्या कृषि पर अत्यधिक निर्भर रहती है। उदाहरण के लिये- मिस्र में 42 प्रतिशत, वर्मा में 50 प्रतिशत, इन्डोनेशिया में 52 प्रतिशत और चीन में 72 प्रतिशत है परन्तु इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में 2-3 प्रतिशत, फ्रांस में 7 प्रतिशत और आस्ट्रेलिया में 6 प्रतिशत कार्यकारी जनसंख्या ही कृषि पर निर्भर है।

इसमें सन्देह नहीं है कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है और कृषि ही वह क्षेत्र है जिसमें व्यापक शक्ति का उपयोग करके अपेक्षित कृषि उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है।[4]

कृषि उत्पादन में वृद्धि करके कृषि पर आश्रित व्यक्ति अपना उपभोग स्तर घटायें बिना बचत करके पूंजी निर्माण में सहायता प्रदान करते है जोकि देश के भावी आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है।[5]

कृषि लगभग सभी उद्योगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है इसलिये कृषि को लगभग सभी उद्योगों की माता या पालन करने वाली कहना अनुचित न होगा।[6] ये उपाधि कृषि को ऐसे नहीं मिली। कृषि देश के प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी उद्योग मुख्यत: कृषि पर ही निर्भर है। खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां भी कृषि पर ही निर्भर है। कृषि का विकास किये बिना इन उद्योगों का विकास भी असंभव है।

देश के अधिकांश लोग खेती में लगे हुये है। पिछड़ी खेती के कारण ये लोग गरीब है और गरीबी के कारण इनकी क्रय शक्ति न्यूनतम है। कृषि विकास के फलस्वरूप इन लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और ये अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार की औधोगिक वस्तुएं खरीद सकने की स्थिति में होगें। जिससे औद्योगिक विकास को अवसर मिल सकेंगे। जिससे राष्ट्रीय आय और रोजगार की मात्रा में वृद्धि होगी। कृषि के विकास के लिये कृषि पर लगी अतिरिक्त जनसंख्या के वहां से हटाकर नए आरम्भ किये गये उद्योगों में लगाया जाना चाहियें। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और अतिरिक्त श्रम शक्ति का उपयोग करके नई औधोगिक इकाइयों की स्थापना की जा सकेगी।[7]

भारतीय कृषि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में बहुत लम्बे समय तक तीन कृषि वस्तुओं (चाय, पटसन, सूती वस्त्रों) का भारत की निर्यात आय में 50 प्रतिशत हिस्सा था। इनमें अन्य कृषि से सम्बन्धित वस्तुओं जैसे-काजू, वनस्पति तेल, चीनी आदि को शामिल कर ले तो कृषि का निर्यात आय में हिस्सा 70 से 75 प्रतिशत तक पहुंच जाता हैं। कृषि वस्तुओं पर इतनी अधिक निर्भरता भारत के अल्प विकास को प्रतिलक्षित करती थी।

आर्थिक विकास के साथ-साथ उत्पादन में विस्तार व विविधीकरण हुआ जिससे निर्यात आय में कृषि का हिस्सा कम हुआ है। उदाहरण हेतु वर्ष 1965-66 में कुल निर्यातो में कृषि निर्यात का हिस्सा 41.6 प्रतिशत था जो वर्ष 2004-05 से घट कर 15 से 20 प्रतिशत की बीच रह गया। देश में कृषि उत्पादन के भारी प्रादेशिक अन्तरों के कारण रेल, मोटर आदि परिवहन साधनों की आय का काफी बड़ा भाग कृषि पदार्थो को एक स्थान से दूसरे स्थाप पर ले जाने से प्राप्त होता है।

कृषि से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को ही भारी राजस्व की प्राप्ति होती है। केन्द्रीय सरकार को निर्यात कर, चाय, तम्बाकू आदि उपजों पर उत्पादन कर तथा राज्य सरकारों को माजगुजारी, सिंचाई कृषि सम्पत्ति कर आदि से भारी राजस्व की प्राप्ति होती है और सरकार अपनी आय का काफी बड़ा भाग कृषि संबंधी कार्यक्रमों के विकास पर व्यय करती है।

अत: यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कृषि की सम्पन्नता पर भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि निर्भर करती है।

1.1 कृषि आधारित उद्योगों की अवधारणा-

"कृषि एवं कृषि आधारित उद्योंगों को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यदि ये उद्योग असफल रहते है तो सरकार एवं राष्ट्र दोनों ही असफल रहेंगे"[8] कृषि आधारित उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। कृषि आधारित उद्योग न केवल किसानों की आयों को बढ़ाने में सहायक है वरन कृषकों को खाली समय में भी बेहतर रोजगार उपलब्ध करने में सहायक है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, "कृषि एवं कृषि उद्योग कुल रोजगार का दो तिहाई भाग प्रदान करते है।" वास्तव में इस क्षेत्र पर ध्यान दिये बिना हम ग्रामीण विकास नही कर सकते है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी और कृषि पर अतिरिक्त श्रम को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाने से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित नही किया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिये ग्रामीण उद्योगों और उनसे संबंधित क्रियाओं का विकास किया जाना परमावश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों का और विस्तार बहुत कुछ कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार प्रसार पर निर्भर करेगा। इन उद्योगों का प्रमुख अंश विनिर्माण क्षेत्र है जिनमें कृषि आधारित उद्योग वस्त्र उद्योग, निर्माण पदार्थो में लगे उघोग शामिल है। शहरी क्षेत्रों में बड़ें पैमानें के उद्योगों में अधिक रोजगार के प्रसार की सम्भावनायें नजर नही आतीं परन्तु लघु क्षेत्र में रोजगार अवसर पैदा करने की बहुत सम्भावनायें है।[9]

कृषि आधारित उद्योग शक्ति अर्थव्यवस्था के विक्रेन्द्रीकरण और सन्तुलन को बनाने में शक्तिशाली यन्त्र की भांति कार्य करते है और कृषि और उद्योगों के मध्य पिछड़े और विकसित उद्योगों के बीच बड़े स्तर पर

खाई पाटने का कार्य करते है। "ग्रामीण औद्योगिकरण, ग्रामीण विकास और समृद्धि की सूचक है।[10]" ये उद्योग गांवो से शहरों में होने वाले पलायन को रोककर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करते है। ये उद्योग बड़े पैमाने पर तत्काल काम जुटाते है, राष्ट्रीय आय के अपेक्षाकृत अधिक न्यायपूर्ण वितरण का आश्वासन देते है, पूंजी और कौशल के साधनों को प्रभावशाली ढंग से गति देते है और ग्रामीणों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाते है।"[11] ग्रामीण औद्योगिकरण ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों मे फैली अत्यधिक बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रयोग को जिला स्तर पर घरेलू बाजारों में प्रयोग किया जा सकता है। केवल परम्परागत पद्धति ही काफी नहीं है बल्कि उन्नत तकनीक और वित्त संबंधी सुविधा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है।[12]

कृषि आधारित उद्योगों की अवधारणा केवल उन लोगों की सीमा तक नही बंधी है जोकि कृषि उपज तथा उसके कच्चे माल (फसलें, गन्ना, तिलहन, फल और खाद्य –सब्जियों, कपास, जूट और संबंधित उत्पादों) प्रक्रिया से प्राप्त होते है। बल्कि वे उद्योग भी जोकि कृषि आदानों को उत्पन्न करने मे मदद करते है जिनमें उर्वरक, कीटनाशक, और कृषि संयंत्र आदि आते है। दूसरे शब्दों में कृषि आधारित उद्योगों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है।[13]

- कृषि में बड़े स्तर पर आदानें का प्रोत्साहन
- कृषि उत्पादों और निर्गतों में बेहतर प्रक्रिया और परिवर्तन करना।
- तैयार माल की तुरन्त खपत को प्रोत्साहन
- कृषि उत्पादन में वृद्धि

इस प्रकार कृषि आधारित उद्योग केवल कच्चे माल के लिये ही कृषि पर निर्भर नही है बल्कि वे कृषि निर्गतों को उत्पन्न करने में सहायक कृषि संयंत्र, उर्वरक, खाद, कीटनाशकों के लिये बाजार पर भी निर्भर है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में जहां श्रम का आधिक्य है और पूंजी की न्यूनता, श्रम आधारित उत्पादन पर ध्यान देकर बेरोजगारी से मुक्ति पाई जा सकती है और अर्थव्यवस्था का दीर्घकालीन विकास किया जा सकता है।[14] यह बात तथ्ययुक्त है कि कृषि आधारित उद्योगों में अन्य उद्योगों की अपेक्षा श्रम की ज्यादा खपत है।

वैकया जी के अनुसार खाण्डसारी उद्योग की अपेक्षा तम्बाकू और धान मिलों में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। कृषि आधारित उद्योग, बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है ये उद्योग आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को कम करके आय एवं सम्पत्ति की असमानताओं को कम करने में सहायक है तथा आर्थिक गतिविधियों के विकेंद्रीयकरण के द्वारा प्रादेशिक असंतुलनों को भी कम करते है।[15] बेरोजगारी और गरीबी के अतिरिक्त, एक अन्य गंभीर समस्या जो देश के सामने है, वह कुछ हाथों में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण अथवा धन व आय के असमान वितरण से संबंधित है। यहीं नहीं कि देश में उत्पादन या आय की मात्रा थोड़ी है, बल्कि उसके वितरण मे भारी असमानता भी है। इस असमानता के आर्थिक एवं आर्थिकेतर परिणाम निस्सदेंह बहुत हानिकारक होते है। यही कारण है हमारे आयोजकों ने भी गरीबी व बेरोजगारी दूर करने के साथ-साथ आर्थिक शक्ति अथवा धन व आय के समान वितरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया है।

इस संबंध में कृषि आधारित उद्योगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने के उद्योगों से आर्थिक शक्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाती है और असमानताएं बढ़ती जाती है। इसके विपरित कृषि आधारित उद्योग समानता का वातावरण तैयार करते है। यह आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकते है तथा अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम करते है। आर्थिक शोषण की संम्भावनाऐं इनके द्वारा कम हो जाती है। इनके द्वारा समानता को निम्न तीन तरह से बढ़ावा मिलता है :-

- उत्पादन का अधिकांश भाग मजदूरी आय के रूप में बंटता है।
- वितरण अधिक से अधिक लोगों के बीच होता है।
- आय का वितरण बहुत विस्तृत क्षेत्र में होता है।

इन उद्योगों के द्वारा देश की जनसंख्या के अधिकांश भाग को लाभ पहुंचता है। ये उद्योग श्रम प्रधान होते है और बिना किसी विशेष कठिनाई के इन्हे अधिकांश स्थानों पर आसानी से चलाया जा सकता है। इन उद्योगों से निम्नलिखित दोहरे लाभ होते है :-

- इन उद्योगों के सहारे अधिक लोगो को रोजगार का मिलना सम्भव बन जाता है।
- यह कमाई उत्पादन कार्य के बल पर होती है।

इस प्रकार हमारे आयोजन के मूल उददेश्य "विकास और सामाजिक न्याय को पूरा किया जा सकता है 16। ग्रामीण विकास में कृषि आधारित उद्योग स्थाई तथा तुरन्त रोजगार उपलब्ध कराते है। प्रश्न केवल ग्रामीण विकास ही नही बल्कि दोनों का है, "उद्योगों को कृषि की आवश्यकता है जबकि कृषि को भी उद्योगों की आवश्यकता है 17।

कृषि सभी ग्रामीण क्रियाओं का केन्द्र है। परन्तु तेज विकास, उद्योगों के साथ ही सम्भव है लेकिन कृषि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नकद फसल जैसे-गन्ना, कपास, जूट, तम्बाकू इत्यादि औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते है। वास्तव में कृषि आधारित उद्योग कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते है। प्रो० अन्जारिया के अनुसार, सभी प्रक्रिया उद्योग कृषि आधारित उद्योग होते है परन्तु निर्माणी उद्योगों में इनकी सीमा निश्चित है। इन्होनें कृषि आधारित उद्योंगों के विषय में बहुत सारी जानकारी दी है। वे कहत है कि "कृषि आधारित उद्योग का सम्बन्ध कृषि उत्पाद तथा उसके अपक्षय की प्रक्रिया से है। ये उद्योग ने केवल फलों व अन्य कृषि उत्पादों को प्रक्रिया में लाते है बल्कि ये उन्हे संग्रह के लिये भी सुविधा प्रदान करती है।"[18] इस प्रकार कृषि आधारित उद्योगों में धान-मिल आदि ही नही बल्कि कृषि को रसायन (उर्वरक एवं कीटनाशक) प्रदान करने वाले उद्योग भी आते है।[19]

किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास उस क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत पाये जाते है। ये क्षेत्र मिट्टी, मौसम, खनिज, जंगल, नदियाँ, प्राकृतिक दशा, मानवीय क्षमता, कृषि उपज के आधार पर भिन्न है। ये समस्त प्राप्त स्रोत विभिन्न प्रकार से औघोगिक प्रयोगों में काम आते है। ये स्रोत आधारित उद्योग, कृषि आधारित खनिज आधारित, पशुपालन, जंगल आधारित, चारा आधारित, मुर्गी पालन कहलाते है।[20]

SAMPLE